

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1513
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में भूजल स्तर

1513. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान भूजल स्तर के आंकड़ों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पानी में प्रदूषण कृषि पद्धतियों, जिसमें उर्वरकों का उपयोग शामिल हैं, के कारण होता है और पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा अन्य स्रोतों से प्रदूषण को कम करने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक जैसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?
- (ङ) जल स्तर मापने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग सहित भूजल निगरानी नेटवर्क के विस्तार में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने मानीटरिंग कुओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में चार बार बोडो भूमि, प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) सहित क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में भूमि जल स्तर की मानीटरिंग करता है।

बोडोलैंड भू-भागीय क्षेत्र के संबंध में पिछले पांच वर्षों (2020-2024) की अवधि के लिए मापे गए जिलेवार भूजल स्तर का उल्लेख अनुलग्नक में दिया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में बोडोलैंड क्षेत्र में भूजल स्तर वर्ष 2024 को छोड़कर, विश्लेषण किए गए लगभग 100% कुओं में 0-10 एमबीजीएल (जमीनी स्तर से नीचे मीटर) के बीच रहा है, जो भूजल तक पहुंचना सुगम बनाता है।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं: -

- i. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए वर्ष 2024 को लागू किया जा रहा है, जिसमें बीटीआर में बक्सा और उदलगुडी जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक संयुक्त अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- ii. इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने असम राज्य में लगभग 61,826 वर्ग किमी सहित देश भर में लगभग 25 लाख वर्ग किमी मैप करने योग्य क्षेत्र का राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना भी पूरी कर ली है। बोडोलैंड क्षेत्र सहित सभी जिलों के लिए जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। एनएक्यूआईएम के तहत तैयार की गई जलभृत प्रबंधन योजनाओं में आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें अनुमानित लागत के साथ लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल के दोहन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार, वर्ष 2015-16 से असम सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना लागू कर रहा है इस स्कीम में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम में 44,356 हेक्टेयर क्षेत्र को स्कीम के अंतर्गत कुशल सिंचाई पद्धतियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- v. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य असम सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना

था। परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ जीर्णोद्धार किया गया है, जिनमें से 2,966 असम में (379 बोडोलैंड क्षेत्र में) हैं।

- vi. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी करके विनियमित किया जाता है, जिनकी अखिल भारतीय प्रयोज्यता है।

(ग): यह समझा जाता है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग जैसी विभिन्न कृषि पद्धतियों से भू-जल में रासायनिक अवशेषों के घुलने के कारण उसमें संदूषण होता है विशेषकर नाइट्रेट का। अन्य मानवीय गतिविधियों जैसे अनुचित ग्रे वाटर प्रबंधन, खुले में शौच आदि को भी भूजल संदूषण का कारण माना जाता है।

(घ): जल राज्य का विषय होने के बावजूद, भूजल संदूषण को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नियमित गुणवत्ता मानीटरिंग और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ डेटा साझा करना, आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं का निर्माण करना और प्रौद्योगिकी का प्रसार, जल आदि में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन आदि।

लेकिन दूषित जल के प्रतिकूल प्रभावों से देश की पूरी आबादी को बचाने के लिए प्रमुख उपाय, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल के कार्यान्वयन के माध्यम से एक श्रेष्ठ पहल के रूप में प्रदान किया गया है। जेजेएम अगस्त 2019 से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक राज्यों सहित देश में कार्यान्वित है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल से जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस मानकों को नल जल सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है और जेजेएम दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित स्थानों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाए।

(ड): सीजीडब्ल्यूबी वर्तमान में लगभग 27,000 स्टेशनों के माध्यम से भूजल स्तर और लगभग 17,000 स्टेशनों के माध्यम से गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है। तथापि, वास्तविक समय आधार पर भूजल के संबंध में उच्च बारंबारता आंकड़े रखने के महत्व को महसूस करते हुए, इस मंत्रालय ने भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना, अटल भूजल योजना आदि जैसी अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत पूरे देश में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत उक्त कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकारों को भी वित्तपोषित किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत देश भर में अब तक लगभग 24,000 डीडब्ल्यूएलआर स्थापित किए गए हैं जो भूजल संबन्धित वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है।

अनुलग्नक

"बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1513 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों (2020-2024) की अवधि के लिए मापा गया जिलावार भूजल स्तर

मानसून 2024 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्सा	17	2	11.8	7	41.2	4	23.5	4	23.5	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	7	3	42.9	3	42.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	9	3	33.3	6	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	19	11	57.9	6	31.6	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	52	19	36.5	22	42.3	7	13.5	4	7.7	0	0.0	0	0.0

मानसून 2023 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्सा	6	2	33.3	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	7	1	14.3	5	71.4	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	11	0	0.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	24	9	37.5	12	50.0	3	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	48	12	25.0	31	64.6	5	10.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

मानसून 2022 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
---------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	कुओं की संख्या	0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्स	6		1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	5		0	0.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	12		0	0.0	11	91.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	15		8	53.3	6	40.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
	कुल	38		9	23.7	25	65.8	4	10.5	0	0.0	0	0.0

मानसून 2021 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र. सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्स	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	4	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	9	0	0.0	8	88.9	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	13	6	46.2	7	53.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	29	8	27.6	20	69.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

मानसून 2020 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की का गहराई प्रतिशत

क्र. सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्स	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	5	1	20.0	3	60.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	10	5	50.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	19	8	42.1	10	52.6	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
